PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 221
दि. 15.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

केरल में कांग्रेस का नया अध्याय : वीडी सतीशन के हाथों में सत्ता, दस दिन की माथापच्ची के बाद लगा नेतृत्व पर मुहर

केरल की राजनीति में लंबे इंतजार, अंदरूनी मंथन और सत्ता के गलियारों में चली लगातार बैठकों के बाद आखिरकार कांग्रेस ने वह फैसला कर लिया, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के दस दिन बाद कांग्रेस नेतृत्व ने वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही राज्य की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में आधिकारिक प्रेस वार्ता कर उनके नाम का एलान किया और साफ संकेत दिया कि पार्टी अब केरल में नई पीढ़ी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर गहन चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में थे और अंतिम समय तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताएगी। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही केरल कांग्रेस के विभिन्न गुट सक्रिय हो गए थे। पार्टी के भीतर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और हर खेमे की कोशिश थी कि उसका नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान पूरे मामले को बेहद सावधानी से संभाल रहा था, क्योंकि पार्टी किसी भी तरह के अंदरूनी विवाद या असंतोष का संदेश जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती थी।

आखिरकार कई दौर की बातचीत और रायशुमारी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंतिम फैसला लिया। कांग्रेस महासचिव K. C. Venugopal भी इस पूरी प्रक्रिया में लगातार सक्रिय रहे। दिल्ली में हुई बैठकों में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के साथ विस्तार से चर्चा की। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राज्य की राजनीतिक स्थिति और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने पार्टी विधायकों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि

सभी ने एकजुट होकर पार्टी के निर्णय का समर्थन किया।

कांग्रेस सांसद Hibi Eden ने भी इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने केरल की जनता की भावना का सम्मान किया है। उनके मुताबिक, विपक्ष के नेता के तौर पर वीडी सतीशन ने पिछले दस वर्षों के एलडीएफ शासन के खिलाफ जिस मजबूती और आक्रामकता के साथ संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के भीतर भी यह माना जा रहा है कि सतीशन ने विपक्ष के नेता रहते हुए खुद को राज्य के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल कर लिया था।

V. D. Satheesan का राजनीतिक सफर संघर्ष, संगठन और प्रभावशाली नेतृत्व का उदाहरण माना जाता है। कोच्चि जिले से आने वाले सतीशन पेशे से वकील रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2001 में पहली बार परवूर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में मजबूत पहचान बनाई थी। विधानसभा के भीतर उनके भाषणों की शैली, तथ्यों और आंकड़ों के साथ विपक्ष को घेरने की क्षमता तथा सरकार पर तीखे हमले करने की शैली ने उन्हें जल्द ही कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बना दिया। उनके समर्थकों का मानना है कि वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि संगठन को नई ऊर्जा देने वाले रणनीतिकार भी हैं।

सतीशन का सबसे बड़ा राजनीतिक उभार वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिला। उस चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ को करारी हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी गहरे संकट में दिखाई दे रही थी। ऐसे समय में कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। शुरुआत में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें एक समझौता उम्मीदवार माना, लेकिन सतीशन ने अपनी राजनीतिक शैली और आक्रामक रणनीति से इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एलडीएफ सरकार को लगातार विभिन्न मुद्दों पर घेरा और खुद को राज्य में सबसे मुखर विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया।

सोना तस्करी मामला, एआई कैमरा विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan और उनकी सरकार पर लगातार हमला बोला। विधानसभा के भीतर और बाहर उनकी सक्रियता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भीतर नया उत्साह पैदा किया। यही कारण रहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में यूडीएफ गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 140 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं सीपीआईएम नीत एलडीएफ गठबंधन केवल 35 सीटों तक सिमट गया और एनडीए को महज तीन सीटों से संतोष करना पड़ा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि केरल की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन का भी संकेत है। कांग्रेस लंबे समय से राज्य में ऐसे चेहरे की तलाश कर रही थी, जो संगठन को एकजुट रखते हुए जनता के बीच मजबूत पकड़ बना सके। वीडी सतीशन को उसी प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। साथ ही, उनकी साफ-सुथरी छवि और आक्रामक विपक्षी राजनीति ने उन्हें जनता के बीच भी लोकप्रिय बनाया है।

मुख्यमंत्री नामित किए जाने के बाद वीडी सतीशन ने कहा कि केरल में अब एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है और उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि नई सरकार केरल को नई दिशा देने में सफल होगी। सतीशन ने यह भी बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उन्हें फोन कर बधाई दी और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पहले पार्टी और गठबंधन के नेताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

दिल्ली में हुई इस घोषणा के बाद केरल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल दिखाई दिया। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटीं और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। कांग्रेस के भीतर यह संदेश भी गया कि हाईकमान ने अंततः उस नेता पर भरोसा जताया है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में सड़क से लेकर विधानसभा तक पार्टी की लड़ाई का नेतृत्व किया। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी जारी है कि मुख्यमंत्री चयन में हुई देरी ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद दस दिन तक चली बैठकों और लॉबिंग ने यह संकेत दिया कि पार्टी के भीतर कई दावेदार मौजूद थे और नेतृत्व को संतुलन साधने में काफी समय लगा।

महंगाई की मार से कराहता बाजार : तेल, चाय, मसाले से लेकर साबुन शैंपू तक सब महंगा, थोक महंगाई ने तोड़ा 42 महीनों का रिकॉर्ड

देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते वैश्विक दबाव और पश्चिम एशिया में गहराते तनाव का असर अब सीधे आम आदमी की रसोई और जेब तक पहुंच चुका है। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं और बाजार में कीमतों की नई लहर ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। चायपत्ती से लेकर खाद्य तेल, मसाले, सूखे मेवे, साबुन, शैंपू और टूथपेस्ट तक लगभग हर जरूरी सामान की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। इसी बीच जारी आंकड़ों ने स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। अप्रैल 2026 में थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई आधारित महंगाई दर बढ़कर 8.30 प्रतिशत पहुंच गई, जो पिछले 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इससे पहले मार्च में यही दर 3.88 प्रतिशत थी। यानी केवल एक महीने के भीतर थोक महंगाई लगभग दोगुनी हो गई।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में और बड़ी महंगाई की चेतावनी भी है। थोक महंगाई में तेज उछाल का सीधा असर धीरे-धीरे खुदरा बाजार और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। यही कारण है कि अब बाजार में लगभग हर उत्पाद की कीमत बढ़ती दिखाई दे रही है। उपभोक्ता सामान बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने पिछले दो महीनों में चुपचाप अपने उत्पादों की कीमतों में 10 से 30 प्रतिशत

तक की बढ़ोतरी कर दी है। कई कंपनियों ने पहले पैकेट का आकार छोटा किया और अब धीरे-धीरे कीमतें भी बढ़ानी शुरू कर दी हैं।

बाजार में सबसे ज्यादा असर खाद्य वस्तुओं पर दिखाई दे रहा है। मार्च के अंत तक जो ब्रांडेड चायपत्ती का एक किलो पैकेट लगभग 500 रुपये में बिक रहा था, उसकी कीमत पहले 515 रुपये की गई और अब कई स्टोर तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वही पैकेट 539 से 545 रुपये तक पहुंच चुका है। यही स्थिति मसालों, सूखे मेवों और अन्य रसोई उत्पादों की भी है। घरेलू बजट संभालने वाली महिलाओं का कहना है कि हर सप्ताह बाजार में कोई न कोई वस्तु महंगी मिल रही है और अब महीने का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है।

खाद्य तेल की कीमतों में आई तेजी ने सबसे अधिक चिंता पैदा की है। बीते दो महीनों में कई प्रमुख ब्रांडों के तेल 20 से 30 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। जिन कंपनियों ने सीधे कीमत नहीं बढ़ाई, उन्होंने बोतल या पैकेट का आकार कम कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में खाद्य तेल और महंगा हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ रहा है।

आंकड़ों के अनुसार भारत हर वर्ष लगभग 16 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात करता है, जिस पर करीब 1.61 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब यदि डॉलर मजबूत होता है और कच्चे तेल के साथ-साथ खाद्य तेल की वैश्विक कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो इसका असर भारतीय बाजार पर और गहरा होगा। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में रसोई का बजट और दबाव में आ सकता है।

महंगाई की मार केवल खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं है। दैनिक उपयोग के उत्पाद भी लगातार महंगे हो रहे हैं। मसालों की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। हेयर ऑयल 7 से 10 प्रतिशत महंगे हुए हैं, टूथपेस्ट की कीमतों में 5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। सूखे मेवों में 15 से 25 प्रतिशत तक की तेजी देखी जा रही है। साबुन और शैंपू जैसी वस्तुएं भी अब पहले की तुलना में अधिक कीमत पर बिक रही हैं। इन बढ़ती कीमतों का असर सीधे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि यही वर्ग रोजमर्रा की वस्तुओं पर सबसे अधिक निर्भर होता है।

महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में आया उछाल भी है। फरवरी के बाद से प्लास्टिक दानों की कीमतों में 30 से 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीपी और पीई ग्रेड के प्लास्टिक दाने ढाई महीनों में दो से चार हजार रुपये प्रति टन तक महंगे हुए हैं। इसका सीधा असर पैकेजिंग उद्योग पर पड़ा है। पैकेजिंग सामग्री की औसत कीमतें 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं, जबकि कुछ मामलों में यह वृद्धि 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है। टिन और मेटल कंटेनर भी 5 से 15 प्रतिशत तक महंगे हुए हैं और कांच की बोतलों की कीमतों में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

एफएमसीजी कंपनियों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि उनके कुल खर्च का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा पैकेजिंग पर खर्च होता है। जब पैकेजिंग सामग्री महंगी होती है तो कंपनियां अंततः उसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालती हैं। यही कारण है कि साबुन, शैंपू, तेल, बिस्किट और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है।

हार की जिम्मेदारी लेकर भावुक हुए स्टालिन : 'सुनामी' बनी टीवीके, अब संगठन को फिर से खड़ा करने की चुनौती

तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद शुरू हुआ मंथन अब खुलकर सामने आने लगा है। चुनावी हार के बाद पहली बार M. K. Stalin ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने भावुक लेकिन स्पष्ट संदेश देते हुए हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में जिला सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि जब कोई नेता जीत का श्रेय ले सकता है, तो हार की जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्टालिन के इस बयान को डीएमके के भीतर आत्ममंथन और संगठनात्मक पुनर्गठन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित हार के बाद डीएमके पहली बार इतने गंभीर राजनीतिक संकट का सामना करती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर चुनाव परिणामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी और यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि हार के बाद यह पहली बड़ी संगठनात्मक समीक्षा बैठक थी। बैठक में मौजूद नेताओं और जिला सचिवों के सामने स्टालिन ने जिस स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी, उसने यह संकेत दिया कि पार्टी अब केवल बहाने खोजने के बजाय जमीनी स्तर पर पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि हार के बाद दोषारोपण की राजनीति में उलझने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा, "जब मैं जीत पर गर्व करता हूं, तो मुझे हार की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।" उनके इस बयान को पार्टी कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से सुना और इसे नेतृत्व की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के रूप में देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण भारतीय राजनीति में अक्सर हार के बाद नेतृत्व स्तर पर इस तरह की खुली जिम्मेदारी स्वीकार करने के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में स्टालिन का यह रुख डीएमके के भीतर संदेशात्मक राजनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बैठक के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस टिप्पणी की हुई, जिसमें स्टालिन ने Tamilaga Vettri Kazhagam यानी टीवीके के चुनावी उभार को "जादुई सुनामी" बताया। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक लहर ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया और डीएमके सहित कई स्थापित राजनीतिक ताकतों को व्यापक नुकसान पहुंचाया। हालांकि उन्होंने इसे स्थायी राजनीतिक बदलाव मानने से इनकार किया और कहा कि यह केवल एक चुनावी लहर थी, न कि डीएमके के राजनीतिक भविष्य का अंत। स्टालिन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें अब जनता के बीच और अधिक सक्रिय होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, उसी तरह पार्टी को भी इस राजनीतिक "सुनामी" से जनता और संगठन दोनों को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। उनके अनुसार, चुनावी हार किसी आंदोलन का अंत नहीं होती, बल्कि वह संगठन की कमजोरियों को पहचानने और खुद को मजबूत करने का अवसर भी देती है। डीएमके अध्यक्ष ने संगठनात्मक एकता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पार्टी की असली ताकत उसका जमीनी ढांचा और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जिला सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी आंदोलन केवल एक नेता के सहारे नहीं चलता, बल्कि हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसकी रीढ़ होता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कोई इमारत अपने सभी स्तंभों के सहारे खड़ी रहती है, उसी प्रकार पार्टी भी हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता के योगदान से मजबूत बनती है। स्टालिन ने साफ संदेश दिया कि पार्टी में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करने को तैयार नहीं हैं, वे स्वयं अलग हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्टालिन का यह बयान केवल संगठनात्मक अनुशासन की बात नहीं थी, बल्कि यह उन नेताओं और गुटों को अप्रत्यक्ष चेतावनी भी थी, जो चुनावी हार के बाद अंदरखाने असंतोष या गुटबाजी में सक्रिय बताए जा रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद डीएमके के भीतर कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में स्टालिन ने एकता और अनुशासन का संदेश देकर संगठन को नियंत्रित रखने की कोशिश की है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पार्टी की आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया को लेकर की गई। स्टालिन ने कहा कि डीएमके अब राज्यव्यापी क्षेत्रीय अध्ययन अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी की हार के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी मुख्यालय एक विशेष समिति का गठन करेगा, जो तमिलनाडु के विभिन्न जिलों का दौरा करेगी और कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं तथा आम जनता से बातचीत कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। यह समिति बीस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर संगठनात्मक और राजनीतिक सुधारों की दिशा तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस समीक्षा में केवल चुनावी रणनीति ही नहीं, बल्कि उम्मीदवार चयन, गठबंधन प्रबंधन, जमीनी संगठन, सोशल मीडिया रणनीति और जनता के बीच पार्टी की छवि जैसे मुद्दों का भी अध्ययन किया जाएगा। डीएमके नेतृत्व यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वह कौन से कारण रहे जिनकी वजह से पार्टी जनता का भरोसा बनाए रखने में विफल रही और टीवीके जैसी नई राजनीतिक शक्ति इतनी तेजी से उभरने में सफल हुई।

देशभर में मतदाता सूची की सबसे बड़ी कवायद शुरू : 19 राज्यों-यूटी में घर घर पहुंचेगा चुनाव आयोग, 36 करोड़ से ज्यादा वोटरों का होगा सत्यापन

देश में आगामी चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में Election Commission of India ने एक बड़ा और व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। गुरुवार को आयोग ने 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि 30 मई से 23 दिसंबर के बीच करोड़ों मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान को देश के सबसे बड़े चुनावी सत्यापन अभियानों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इसके तहत 36.73 करोड़ मतदाताओं की जानकारी दोबारा जांची और अपडेट की जाएगी।

निर्वाचन आयोग के अनुसार यह विशेष गहन पुनरीक्षण केवल एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र और वास्तविक मतदाताओं के नाम शामिल रहें, जबकि मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें। इसके साथ ही नए मतदाताओं को भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

तीसरे चरण के तहत जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जाएगा, उनमें दिल्ली, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नगालैंड, त्रिपुरा तथा दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शामिल हैं। आयोग ने बताया कि यह पूरा कार्यक्रम देश में चल रही जनगणना की घर-घर सूचीकरण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि दोनों प्रक्रियाओं के बीच समन्वय बना रहे और डेटा की सटीकता बढ़ाई जा सके।

इस विशाल अभियान को सफल बनाने के लिए आयोग ने बड़े पैमाने पर मानव संसाधन भी तैनात किए हैं। लगभग 3.94 लाख बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र करेंगे। उनके साथ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए भी सहयोग करेंगे। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सहभागी तरीके से पूरी हो सके। चुनाव आयोग का मानना है कि राजनीतिक दलों की भागीदारी से मतदाता सूची को लेकर विवाद और शिकायतें कम होंगी तथा सभी पक्षों का भरोसा मजबूत होगा।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के दौरान बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर उनकी पहचान, पते और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन करेंगे। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने स्थायी रूप से स्थान बदला है या जो किसी अन्य कारण से अपात्र हो गए हैं, उनके रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। साथ ही नए पात्र मतदाताओं को भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की जमीनी मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मतदाता सूची की सटीकता ही चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता का आधार होती है।

आयोग ने यह भी बताया कि पहले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। उन चरणों में 6.3 लाख से अधिक बीएलओ और करीब 9.2 लाख बीएलए विभिन्न स्तरों पर शामिल रहे थे। चुनाव आयोग का दावा है कि अब तक की प्रक्रिया में मतदाता सूचियों को अधिक अद्यतन और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

तीसरे चरण के कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों में प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। आयोग के अनुसार ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जुलाई को किया जाएगा, जबकि अंतिम सूची 6 सितंबर को जारी होगी। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय जैसे राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 7 अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी। इन तिथियों के बीच मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा, ताकि किसी त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिन राज्यों में यह पुनरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है, उनमें कई ऐसे राज्य शामिल हैं जहां आने वाले समय में विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों की संभावना है। ऐसे में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक दलों की नजरें इस पूरी प्रक्रिया पर टिकी रहेंगी। चुनावी राजनीति में अक्सर फर्जी वोटरों, डुप्लीकेट नामों और मतदाता सूची से नाम हटने जैसे मुद्दों पर विवाद होता रहा है। इसी कारण चुनाव आयोग इस बार तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर अधिक सतर्क दिखाई दे रहा है।

चुनाव आयोग का यह कदम ऐसे समय आया है, जब देश में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर लगातार बहस होती रही है। आयोग की कोशिश है कि घर-घर सत्यापन के जरिए मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जाए और नागरिकों का भरोसा मजबूत किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यदि यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूरी होती है तो इससे चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता काफी बढ़ सकती है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां अलग से यह चरण लागू नहीं होगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। वहीं असम में अलग से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था।

चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण केवल तकनीकी कार्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करने की प्रक्रिया है। यदि सूची में त्रुटियां रहती हैं तो चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बार बड़े पैमाने पर बूथ स्तर तक निगरानी और सत्यापन की व्यवस्था कर रहा है। देश में चुनावों को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया माना जाता है। ऐसे में 36 करोड़ से अधिक मतदाताओं का सत्यापन केवल प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे को अद्यतन और मजबूत बनाए रखने की राष्ट्रीय कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में यह प्रक्रिया न केवल चुनाव आयोग की कार्यक्षमता की परीक्षा होगी, बल्कि राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी का भी बड़ा परीक्षण साबित होगी।

संपादकीय

मानवता के प्रति अपराध है घटिया औषधि

पिछले दिनों सामने आई वह खबर विचलित कर गई कि दिल और रक्तचाप नियंत्रण की दवाइयों में गुणवत्ता की गिरावट पायी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ की ओर से मार्च माह के लिए जारी ड्रग अलर्ट में देश में बनी कई दवाइयों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट डराती है कि कुल 141 दवाओं के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इनमें शुगर, हार्ट, उच्च रक्तचाप, मिर्गी जैसे गंभीर रोगों का उपचार करने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। इनमें इंजेक्शन व कफ सिरप भी शामिल हैं। कमोबेश यही स्थिति विटामिन व आयरन की गोलियों की भी रही। जिन राज्यों में उत्पादित घटिया दवाओं का खुलासा हुआ, उनमें हिमाचल प्रदेश पहले पायदान पर रहा, फिर उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आदि राज्य शामिल हैं। यानी एक-दो राज्य नहीं, तमाम राज्यों के दवा उत्पादक इस अपवित्र कर्म में शामिल हैं। यूं कहें कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है। विडंबना देखिए कि कफ सिरप के 17 नमूने फेल हुए हैं। अब यह साफ हो गया कि अफ्रीका व सेंट्रल एशिया के कुछ देशों तथा भारत के कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के जो आरोप भारतीय दवा कंपनियों पर लगे थे, वे गलत नहीं थे, जिससे पूरी दुनिया में भारतीय दवा उद्योग की छवि खराब हुई। इतना ही नहीं, टूथपेस्ट, मेहंदी व साबुन के नमूने तक फेल हुए हैं। कह सकते हैं कि दवा के नाम पर दर्द देने का कारोबार देश के विभिन्न भागों में खूब फल-फूल रहा है, जो नियामक एजेंसियों की कारगुजारियों पर सवाल उठाता है। कह सकते हैं कि यह अब सिर्फ स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं रहा, यह जिंदगियों से खिलवाड़ के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाता है।

निस्संदेह, घटिया दवाओं से किसी का बीमार होना एक व्यक्ति या परिवार की ही त्रासदी नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि कोई व्यक्ति सेहत सुधारने के लिए महंगी दवा का सेवन करे और उपचार के बाद और बीमार हो जाए। ये मरीज के विश्वास के साथ भी छल जैसा है। यह देश में सक्रिय खतरनाक तंत्र की ओर भी इशारा है जो पूरे देश में नकली व घटिया दवाओं के उत्पादन व आपूर्ति से जुड़ा है। वे चिकित्सक भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जो ऐसी संदिग्ध दवाइयां मरीजों के उपचार के लिए लिखते हैं, जिनकी गुणवत्ता को लेकर शंका रहती है। कोरोना काल में हमने देखा था कि चंद रुपयों के लालच में घातक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे गए। कितना शर्मनाक है कि जानलेवा कैंसर की दवाइयों में घटिया व सस्ती एंटी-फंगल दवा मिलाकर बेची जा रही थी। गुरुग्राम में पिछले दिनों वजन घटाने वाले नकली इंजेक्शनों की बड़ी खेप बरामदगी हुई। देश में घातक दवाओं को बेचने वाला एक तंत्र सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। कोई मरे या जीए, उनकी बला से। उन्हें तो अपने मुनाफे से मतलब है। दरअसल, यह संकट एक राज्य का नहीं, पूरे देश के सामने मौजूद है। नियामक एजेंसियों की लापरवाही, कड़े कानूनों का अभाव व दोषियों को समय पर कड़ी सजा न मिलना इस अमानवीय धंधे के फलने-फूलने की वजह बन रहा है। निस्संदेह मानवता के खिलाफ होने वाले इस आपराधिक कृत्य में चिकित्सा तंत्र से जुड़े लोगों की भूमिका भी होगी। घटिया दवाओं का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यवस्था में शामिल काली भेड़ें इस अपवित्र कारोबार को प्रश्रय दे रही हैं। निगरानी तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाकर और कानून के क्रियान्वयन में तेजी लाकर ही स्थिति को संभाला जा सकता है। आज देश में उपभोक्ताओं व मरीजों के तिमारदारों को जागरूक करने की जरूरत है कि वे दवा खरीदते समय मेडिकल स्टोर से बिल लें। दवाओं की पैकेजिंग की जांच-पड़ताल करें। संदेह होने पर संबंधित विभागों को शिकायत करके राष्ट्रीय दायित्व निभाएं। तभी दवा जीवन रक्षा का माध्यम बनी रह सकेगी।

न्याय का चश्मा और पुरुष पीड़ा का मौन प्रतिवाद

> “न्यायप्रिय समाज वही है जहां न्याय ‘लिंग’ नहीं, ‘पीड़ा’ देखकर हो। पुरुष समझें कि उनके आंसू और मानसिक सुकून भी उतने ही कीमती हैं; उनका मन भी कांच जैसा संवेदनशील हो सकता है।

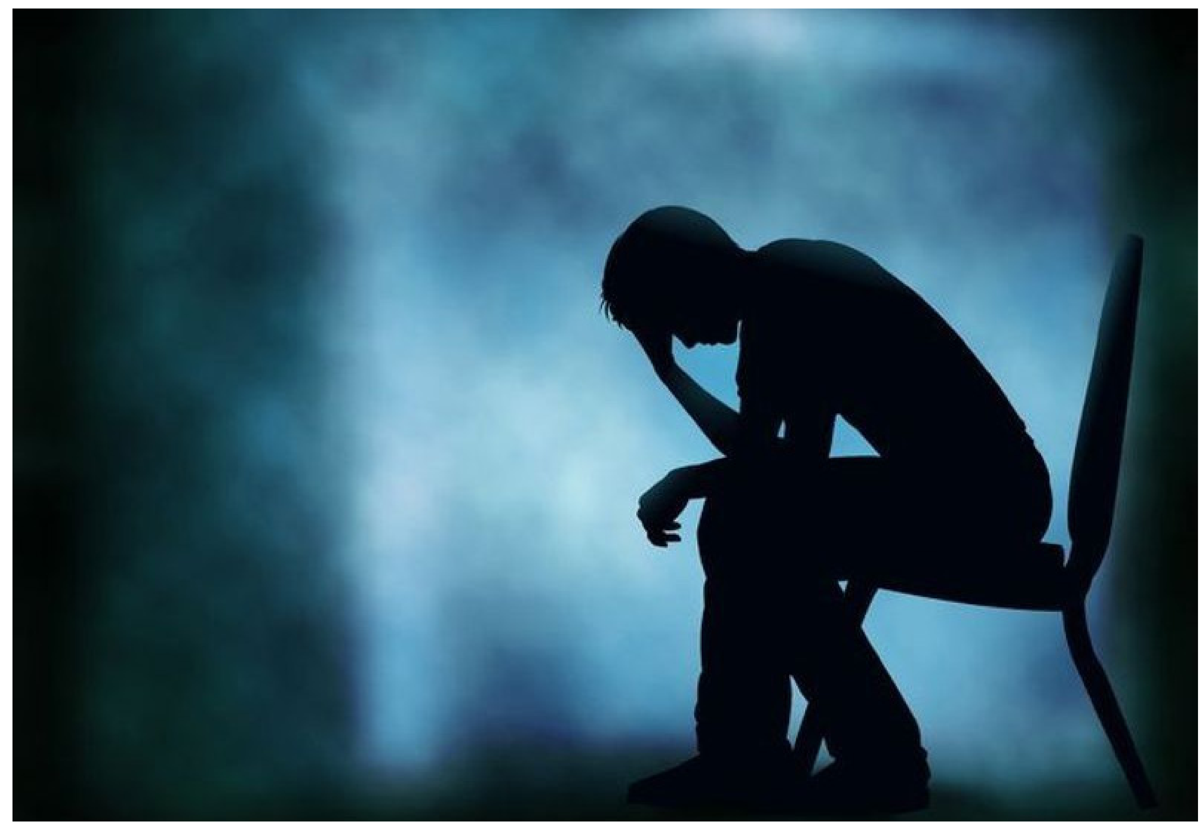

जीवन हारने के लिए नहीं, बल्कि हक के लिए लड़ने के लिए है। हमारे समाज में ‘मर्दानगी’ की खोखली परिभाषा और ‘मर्दों को दर्द नहीं होता’ जैसे संवादों ने पुरुषों के चारों ओर चुप्पी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जहां उनका मानसिक संताप सिसकियों में भी नहीं बदल पाता। अक्सर वैवाहिक प्रताड़ना और ‘लोकलाज’ के डर से पुरुष खामोशी या आत्मघाती कदम चुन लेता है। आज समय की मांग है कि हम पुरुष मानसिक उत्पीड़न को केवल एक निजी व्यथा न मानकर, इसे एक गंभीर कानूनी और मनोवैज्ञानिक संकट के रूप में स्वीकार करें।

युवा जज अमन शर्मा की आत्महत्या ने न्याय व्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि पद और प्रतिष्ठा मानसिक प्रताड़ना के आगे बौने हैं। जब दूसरों को न्याय दिलाने वाला कानून का ज्ञाता स्वयं को इतना असुरक्षित और असहाय पाकर मौत को गले लगा लेता है, तो यह हमारे तंत्र की गंभीर विफलता को दर्शाता है। विशेषकर ‘लव मैरिज’ जैसे रिश्तों में पुरुष अक्सर उस दोहरे नैतिक दबाव और ‘अपनों के खिलाफ चुनाव’ के बोझ तले दब जाता है, जहां प्रताड़ना सहते हुए भी उसे घर वापसी के रास्ते बंद नजर आते हैं। यह प्रकरण एक भयावह चेतावनी है कि मानसिक यंत्रणा चरम पर होने पर ज्ञान और पद पीछे छूट जाते हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि कानून को ‘जेंडर’ के बजाय ‘पीड़ा’ के चश्मे से देखा जाए।

वर्तमान में सामाजिक और कानूनी ढांचे में जहां महिलाओं के लिए कठोर सुरक्षा तंत्र मौजूद है, वहीं पीड़ित पुरुषों के प्रति अक्सर उदासीनता देखी जाती है। विशेष रूप से धारा 498ए के दुरुपयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ (2005) के मामले में ‘कानूनी आतंकवाद’ की संज्ञा दी है। इसका मुख्य कारण यह है कि पतियों के पास पत्नी द्वारा की गई शारीरिक हिंसा या घर से निकाले जाने की स्थिति में वैसी त्वरित वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

इसके बावजूद, बदलती न्यायिक चेतना अब ‘मानसिक क्रूरता’ के आधार पर पुरुषों को राहत प्रदान कर रही है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आईए) के तहत निरंतर अपमान और प्रताड़ना को तलाक का वैध आधार माना गया है, जबकि धारा 10 के अंतर्गत ‘न्यायिक पृथक्करण’ मानसिक शांति के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झूठे मुकदमों और ब्लैकमेलिंग के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जिससे पुरुष कानूनी बारीकियों का उपयोग कर अपनी गरिमा और अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

भारतीय न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों, विशेषकर नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006)और समर घोष बनाम जया घोष (2007) के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कानून का उद्देश्य केवल किताबी प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करना भी है। इन ऐतिहासिक फैसलों ने ‘मानसिक क्रूरता’ के दायरे को विस्तार देते हुए माना कि यदि वैवाहिक रिश्ता पूरी तरह टूट चुका हो और पति पर वृद्ध माता-पिता को छोड़ने का दबाव बनाना या उसे संतान के सुख से वंचित करना जैसी असहनीय स्थितियां उत्पन्न हों, तो उसे इस बोझिल बंधन से मुक्त होने का पूरा अधिकार है। यह न्यायिक दृष्टिकोण रेखांकित करता है कि न्याय के तराजू में संवेदनशीलता और यथार्थवाद का संतुलन अनिवार्य है, जहां व्यक्ति की मानसिक शांति को वैधानिक औपचारिकताओं से ऊपर स्थान दिया गया है।

विकसित देशों में पुरुष उत्पीड़न को लेकर कानून अधिक संतुलित हैं। यूनाइटेड किंगडम में जबरन नियंत्रण का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जो यह स्वीकार करता है कि पुरुष भी भावनात्मक शोषण के शिकार हो सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और स्कैंडिनेवियन देशों में पुरुषों के लिए विशेष ‘एब्यूज शेल्टर’ और हेल्पलाइन सक्रिय हैं। भारत में भी अब समय आ गया है कि हम अपनी कानूनी धाराओं को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में विचार करें, ताकि न्याय का तराजू किसी एक तरफ न झुके।

व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए केवल कानूनों का संकलन मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए धरातल पर एक नई सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण के सूत्रपात की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें संवाद और सामाजिक साहस को बढ़ावा देना होगा ताकि समाज में व्याप्त इस धारणा को बदला जा सके कि अपनी समस्या साझा करना कमजोरी की निशानी है। ‘लोग क्या कहेंगे’ के डर से ऊपर उठकर यह समझना अनिवार्य है कि आपका जीवन किसी भी सामाजिक लोकलाज से कहीं अधिक कीमती है; यदि कोई रिश्ता बोझ बन जाए, तो उसे घुट-घुटकर ढोने के बजाय सम्मानजनक अलगाव का साहस जुटाना ही बेहतर है।

डिजिटल युग में मौन को अपनी नियति बनाने के बजाय न्याय को अपना मार्ग चुनिए; याद रखिए, आपका जीवन और आत्म-सम्मान किसी भी सामाजिक लोकलाज से कहीं अधिक कीमती है। पूर्वाग्रह मुक्त जांच की नितांत आवश्यकता है। साक्ष्य संचयन केवल कानूनी हथियार नहीं, बल्कि आपकी सच्चाई का प्रमाण है। पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ‘मेंस वेलफेयर’ संस्थाओं और मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रेरणा

परोपकार में छिपा देवत्व का प्रकाश

मानव जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। यदि मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं, अपने सुख और अपने स्वार्थ तक सीमित रह जाए, तो उसका जीवन एक साधारण अस्तित्व बनकर रह जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझने लगता है, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना अपने भीतर जगाता है, तब उसके व्यक्तित्व में एक दिव्यता जन्म लेने लगती है। यही दिव्यता मनुष्य को सामान्य से असामान्य और साधारण से महान बना देती है। संसार के सभी महान धर्मों, दार्शनिकों और संतों ने एक ही बात पर बल दिया है कि परोपकार ही वह मार्ग है, जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में ऊंचाई प्रदान करता है। जिस हृदय में दूसरों के लिए करुणा होती है, वहां ईश्वर का निवास स्वयं होने लगता है।

चीनी महान दार्शनिक Confucius का जीवन इसी सत्य का प्रमाण था। उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के अनुभवों और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि मनुष्य की महानता उसके पद, धन या शक्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने दूसरों के लिए कितना किया। एक बार चीन के सम्राट ने उनसे पूछा कि देवताओं से भी महान कौन हो सकता है। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि मनुष्य की वास्तविक महानता को समझने का प्रयास था। कन्फ्यूशस ने पहले तो सम्राट की सत्य को जानने की इच्छा की प्रशंसा की, लेकिन जब सम्राट ने पुनः वही प्रश्न किया, तब उन्होंने उन्हें एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति के पास ले जाकर उत्तर दिया, जो वृद्धावस्था में भी लोगों के लिए कुआं खोद रहा था। वह दृश्य अत्यंत साधारण था, लेकिन उसके भीतर जीवन का गहरा दर्शन छिपा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी उम्र आराम करने की थी, अपने श्रम से दूसरों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, केवल संतोष और सेवा का भाव था। कन्फ्यूशस ने सम्राट से कहा कि यही व्यक्ति देवताओं से भी महान है, क्योंकि यह अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए समर्पित कर रहा है। यही परोपकार का वास्तविक अर्थ है। जब कोई व्यक्ति अपने सुख, अपने समय और अपने श्रम को दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करता है, तब वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। आज का समय भौतिकता और स्वार्थ से भरा हुआ दिखाई देता है। लोग अपने जीवन को केवल उपलब्धियों, धन और प्रतिष्ठा तक सीमित कर रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है। ऐसे समय में परोपकार की भावना धीरे-धीरे कम होती जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य को वास्तविक शांति केवल दूसरों के लिए कुछ करने से ही प्राप्त होती है। जब कोई भूखा व्यक्ति भोजन पाकर मुस्कुराता है, जब किसी जरूरतमंद को सहायता मिलती है, जब किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर आशा लौटती है, तब जो संतोष मिलता है, वह किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक बड़ा होता है।

परोपकार केवल धन देने का नाम नहीं है। यह एक भावना है, जो मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होती है। कई बार एक मधुर शब्द, एक छोटा सा सहयोग, किसी दुखी व्यक्ति को दिया गया सहारा भी परोपकार बन जाता है। समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं, जो बिना किसी प्रसिद्धि या प्रशंसा की इच्छा के चुपचाप दूसरों की सेवा करते रहते हैं। कोई गरीब बच्चों को शिक्षा देता है, कोई बीमारों की सेवा करता है, कोई पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार तैयार करता है। ये लोग बाहरी रूप से साधारण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में यही समाज के सच्चे नायक होते हैं।

भारतीय संस्कृति में भी परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीतीं और सूर्य अपने लिए प्रकाश नहीं देता। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। यदि प्रकृति केवल अपने लिए जीती, तो संसार का संतुलन कभी बना नहीं रह पाता। इसी प्रकार मनुष्य भी तभी पूर्ण बनता है, जब वह दूसरों के जीवन में सुख और आशा का कारण बनता है।

इतिहास गवाह है कि संसार में जिन लोगों को सबसे अधिक सम्मान मिला, वे वही थे जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। चाहे महात्मा गांधी हों, मदर टेरेसा हों या कोई अनजान समाजसेवी, इन सभी के भीतर एक समान गुण था — दूसरों के दुख को अपना दुख मानना। यही भावना मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। देवता इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भी देने की आदत सीख लेता है, वह धीरे-धीरे उसी दिव्यता का हिस्सा बन जाता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में परोपकार को केवल एक आदर्श न मानें, बल्कि उसे व्यवहार का हिस्सा बनाएं। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प ले ले, तो समाज की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं। परोपकार का अर्थ हमेशा बड़े कार्य करना नहीं होता। किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर देना, किसी बुजुर्ग को सम्मान देना या किसी असहाय व्यक्ति को सहारा देना भी उतना ही बड़ा कार्य है। छोटे-छोटे सद्कर्म मिलकर समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

मनुष्य का जीवन सीमित है। धन, पद और प्रसिद्धि सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए किए गए अच्छे कार्य हमेशा जीवित रहते हैं। लोग किसी व्यक्ति को उसके वैभव से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसके द्वारा किए गए उपकारों से याद रखते हैं। यही कारण है कि परोपकार मनुष्य को अमर बना देता है। जिस व्यक्ति के कारण किसी के जीवन में आशा जागती है, वह वास्तव में ईश्वर के कार्य में सहभागी बन जाता है।

कन्फ्यूशस का वह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। देवत्व किसी आकाश में नहीं छिपा, बल्कि वह मनुष्य के भीतर मौजूद करुणा, सेवा और त्याग की भावना में बसता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि दूसरों के सुख के लिए जीता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। परोपकार ही वह दीपक है, जो मनुष्य के भीतर मानवता का प्रकाश जलाता है और उसे देवत्व के सबसे निकट पहुंचा देता है।

घर पर कितना Gold रखने की इजाजत देती है सरकार? नया सोना खरीदना नहीं है मगर पुराने सोने को रखने के नियम क्या हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अगले एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचने की अपील की। उनका कहना था कि देश को गैर जरूरी आयात कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद देश में एक बार फिर सोना रखने के नियमों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर चर्चा तेज हो गई है। देखा जाये तो भारत में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि बचत, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और बाजार में उतार चढ़ाव के समय लोग सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि गांव से लेकर शहर तक भारतीय परिवारों में सोने की मजबूत मांग बनी रहती है। हालांकि देश में किसी व्यक्ति द्वारा सोना रखने की कोई स्पष्ट कानूनी सीमा तय नहीं है, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने 11 मई 1994 को जारी एक परिपत्र में आयकर अधिकारियों के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। इन निर्देशों का उद्देश्य आयकर छापों के दौरान अनावश्यक विवादों से बचना था। इसके तहत अधिकारियों को एक निश्चित सीमा तक सोने के आभूषण जब्त नहीं करने की सलाह दी गई थी।

सीबीडीटी के नियमों के अनुसार विवाहित महिलाओं के पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण होने पर उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम तय की गई है। वहीं पुरुषों के लिए, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, 100 ग्राम तक सोने के आभूषण रखने की सीमा निर्धारित है। इन सीमाओं के भीतर पाए गए आभूषणों को सामान्य परिस्थितियों में आयकर अधिकारी जब्त नहीं कर सकते।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने सोने का विवरण संपत्ति कर विवरणी में दिया है, या वह सोने के वैध स्रोत का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत कर देता है, तो ऐसे आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पारिवारिक परंपरा, सामाजिक स्थिति और रीति रिवाजों को देखते हुए अधिकारियों को अधिक मात्रा में सोना होने पर भी विवेकाधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है।

लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद सोने का वैध स्रोत नहीं बता पाता, या उसका जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता, तो उस पर भारी कर लगाया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे मामलों में लगभग 78 प्रतिशत तक कर वसूला जा सकता है, जिसमें अधिभार और उपकर भी शामिल होता है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस बीच सोने पर बढ़ी आयात शुल्क दरों ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि आयात शुल्क बढ़ने से सोने की खुदरा कीमतों में तेजी आएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और सीमित बजट वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि निकट भविष्य में सोने की बिक्री में गिरावट देखने को मिल सकती है।

जानकारों का कहना है कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों का लगभग पूरा सोना आयात के जरिये पूरा करता है। वित्त वर्ष 2026 में देश का सोना आयात बढ़कर 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 58 अरब डॉलर था। ऐसे में आयात शुल्क में वृद्धि का सीधा असर कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है।

सेन्को गोल्ड के प्रबंध निदेशक सुवंकर सेन का कहना है कि आयात शुल्क बढ़ने से कीमतों में तत्काल असर दिखाई देगा और कई ग्राहक फिलहाल खरीदारी टाल सकते हैं। उनके अनुसार निकट अवधि में बिक्री की मात्रा में 10 से 15 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। मालाबार समूह के अध्यक्ष एमपी अहमद का कहना है कि पहली बार सोना खरीदने वाले ग्राहकों को नई कीमतों के अनुसार खुद को ढालने में समय लगेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुराने सोने के बदले नया आभूषण लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ेगी और आगे चलकर यही खरीदारी का प्रमुख तरीका बन सकता है। ज्वेलरी कारोबार से जुड़े उद्योगपति डॉ. जॉय अलुक्कास का मानना है कि भारत में शादी और त्योहारों के साथ सोने का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ता है, इसलिए दीर्घकाल में मांग पूरी तरह कमजोर नहीं होगी। उनका कहना है कि अब ग्राहक सोने को केवल गहनों के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखने लगे हैं।

इसी परिस्थिति को देखते हुए कई कंपनियां पुराने सोने के बदले नया आभूषण देने वाली योजनाओं पर जोर दे रही हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने गोल्ड फोर इंडिया नाम से अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहकों को पुराने, टूटे या अनुपयोगी आभूषण बदलकर नया सोना खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही कम शुद्धता वाले 18 कैरेट आभूषणों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कम मात्रा में शुद्ध सोने का उपयोग हो सके।

रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने भी अपने सदस्यों से कम कैरेट वाले आभूषणों की बिक्री बढ़ाने और सोने की ईंटों तथा सिक्कों में निवेश को हतोत्साहित करने की अपील की है। परिषद का मानना है कि सोने की ईंटों और सिक्कों का आयात कुल आयात का लगभग 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा है, जिसे कम करना जरूरी है।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की अपील, आयात शुल्क में वृद्धि और सरकार की निगरानी ने सोने के बाजार को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक ओर सरकार आयात कम कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में सोने की सांस्कृतिक अहमियत के कारण इसकी मांग पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं दिखती। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोने की खरीदारी का तरीका जरूर बदल सकता है, जहां लोग पुराने आभूषण बदलने, हल्के गहने खरीदने और सोच समझकर निवेश करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल, आइये देखते हैं इस पूरे मामले पर ज्वैलर्स क्या कह रहे हैं।

अभियान

ज्येष्ठ का तप, दान और सेवा : मानवता से मोक्ष तक का पुण्यपथ

भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक महीना केवल समय का एक खंड नहीं होता, बल्कि वह प्रकृति, अध्यात्म और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। वैदिक पंचांग का प्रत्येक मास अपने भीतर विशेष ऊर्जा, धार्मिक महत्व और जीवनोपयोगी संदेश समेटे होता है। इन्हीं महीनों में ‘ज्येष्ठ’ का महीना अत्यंत विशिष्ट माना गया है। सामान्य बोलचाल में इसे ‘जेठ’ कहा जाता है, किंतु शास्त्रों में इसका उल्लेख ‘ज्येष्ठ’ नाम से हुआ है। ‘ज्येष्ठ’ शब्द का अर्थ ही होता है — बड़ा, श्रेष्ठ और वरिष्ठ। यह महीना केवल ताप और गर्मी का प्रतीक नहीं है, बल्कि तप, त्याग, सेवा, साधना और परोपकार की महान परंपरा का भी प्रतीक है। प्रकृति जब अपने प्रचंड ताप से संपूर्ण जीव-जगत की परीक्षा लेती है, तब मनुष्य के भीतर छिपी दया, करुणा और सेवा की भावना भी परखी जाती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास को दान, तप, भक्ति और लोककल्याण का महापर्व कहा गया है।

वैदिक ज्योतिष और पंचांग की परंपरा अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म मानी जाती है। हिंदू पंचांग में महीनों का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उसी नक्षत्र के आधार पर महीने का नाम रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के समय चंद्रमा ‘ज्येष्ठा’ नक्षत्र में स्थित रहता है, इसलिए इस महीने को ‘ज्येष्ठ’ कहा गया। यह केवल नामकरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पृथ्वी पर उसके प्रभाव का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने समय की गणना को केवल गणित तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धर्म, प्रकृति और मानव जीवन के साथ जोड़कर देखा।

इस वर्ष ज्येष्ठ मास का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इसमें ‘अधिक मास’ का अद्भुत संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार, यह महीना सामान्य अवधि से अधिक समय तक रहेगा। अधिक मास को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के मध्य जो अंतर उत्पन्न होता है, उसे संतुलित करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास जोड़ा जाता है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि भारतीय कालगणना केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि अत्यंत गहन खगोलीय ज्ञान पर आधारित है। अधिक मास को ‘पुरुषोत्तम मास’ भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित माना गया है। इस अवधि में श्रीविष्णु की आराधना, जप, तप और भक्ति करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

ज्येष्ठ का महीना प्रकृति के सबसे कठिन समय का प्रतीक होता है। सूर्य का प्रचंड ताप धरती को झुलसा देता है। नदियों का जल कम होने लगता है, पशु-पक्षी व्याकुल हो उठते हैं और जीव-जगत पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करता है। ऐसे समय में शास्त्र मनुष्य को केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सेवा और दया का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि इस महीने में जलदान को ‘महादान’ कहा गया है। जिस समय एक बूंद पानी जीवन बचा सकती हो, उस समय किसी प्यासे को जल पिलाना केवल दान नहीं, बल्कि जीवनदान बन जाता है। सनातन संस्कृति में जल को स्वयं देवता माना गया है। जल ही जीवन है और जलदान जीवन की रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम। पुराणों और धर्मग्रंथों में वर्णित है कि ज्येष्ठ मास में मिट्टी के घड़े, सुराही, शरबत, ठंडे पेय, हाथ के पंखे, छाते, वस्त्र, फल और अन्न का दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। इसके पीछे केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि गहरा सामाजिक और मानवीय संदेश भी छिपा है। जब मौसम कठिन हो, तब जरूरतमंद की सहायता करना ही वास्तविक धर्म है। किसी गरीब राहगीर को ठंडा पानी पिलाना, मजदूरों को शरबत बांटना, यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाना या पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना — ये सभी कर्म मनुष्य को भीतर से पवित्र बनाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में जीवों के ताप को हरता है, उसका स्वयं का जीवन भी शांति और समृद्धि से भर जाता है।

सनातन परंपरा में दान केवल वस्तुओं का लेन-देन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना गया है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करता है, तब उसके भीतर अहंकार का क्षय होता है। दान मनुष्य को विनम्र बनाता है और यह अनुभूति कराता है कि संसार में सब कुछ ईश्वर का है। ज्येष्ठ मास इसी भावना को जागृत करता है। यह महीना सिखाता है कि पूजा केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि प्यासे को पानी पिलाने, भूखे को भोजन देने और दुखी को सहारा देने से भी होती है।

ज्येष्ठ मास में पशु-पक्षियों की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब ताप अपने चरम पर होता है, तब पक्षियों के लिए जल और दाना रखना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। घरों की छतों, आंगनों और पेड़ों के नीचे मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवदया का महान कार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मूक प्राणियों की रक्षा करता है, उस पर स्वयं भगवान की कृपा बनी रहती है। गायों के लिए हरा चारा, पशुओं के लिए पानी और पक्षियों के लिए दाना उपलब्ध कराना वास्तव में प्रकृति और मानवता दोनों की सेवा है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। ज्येष्ठ मास में पौधारोपण और जल-स्रोत निर्माण का विशेष महत्व इसी कारण बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति कुआं खुदवाता है, तालाब बनवाता है या वृक्ष लगाता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन का आधार बनते हैं। पीपल, वट और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा का विधान भी इसी महीने में विशेष रूप से बताया गया है। पीपल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है, जबकि वट वृक्ष दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक है। तुलसी को स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। इनकी पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का संदेश भी है। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्यनारायण की उपासना का भी विशेष महत्व है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि उनका प्रकाश और ऊर्जा ही जीवन का आधार है। इस महीने प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सात्विक जीवन अपनाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इसी महीने भगवान श्रीराम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ के मंगलवार भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं।

यह महीना मनुष्य को यह भी सिखाता है कि तप केवल जंगलों में बैठकर साधना करने का नाम नहीं है। वास्तविक तप वह है, जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थों पर नियंत्रण रखकर दूसरों के लिए जीना सीखता है। जब कोई व्यक्ति गर्मी में स्वयं असुविधा सहकर किसी दूसरे को राहत पहुंचाता है, तब वही सच्चा तप बन जाता है। यही कारण है कि ज्येष्ठ मास को आध्यात्मिक उन्नति का महीना कहा गया है। यह मनुष्य के भीतर सेवा, करुणा और त्याग की भावना को जागृत करता है।

आज आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य प्रकृति और संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में ज्येष्ठ मास की परंपराएं हमें पुनः मानवता और करुणा की ओर लौटने का संदेश देती हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस महीने केवल एक छोटा संकल्प ले ले कि वह किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, किसी पशु-पक्षी के लिए जल रखेगा, किसी गरीब को फल देगा या एक पौधा लगाएगा, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की एक नई धारा प्रवाहित हो सकती है।

सनातन धर्म का मूल संदेश ही यही है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि लोककल्याण है। ज्येष्ठ मास उसी लोककल्याण की चेतना को जागृत करता है। यह महीना बताता है कि जब मनुष्य अपने सुख से ऊपर उठकर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचने लगता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक पुण्य का उदय होता है। दान, तप, भक्ति और सेवा का यह संगम ही मनुष्य को भीतर से प्रकाशित करता है और उसे ईश्वर के सबसे निकट पहुंचा देता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सूरत रेलवे स्टेशन बना निर्माण और ट्रैफिक चुनौती का केंद्र : रीडेवलपमेंट के बीच प्रशासन का बड़ा मास्टर प्लान, अगले तीन साल रहेंगे बेहद अहम

Surat का रेलवे स्टेशन क्षेत्र इन दिनों शहर के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन और सबसे कठिन ट्रैफिक संकट—दोनों का केंद्र बन चुका है। एक ओर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस विश्वस्तरीय ट्रांजिट हब में बदलने का महत्वाकांक्षी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर निर्माण कार्य के कारण पूरे इलाके में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सहारा दरवाजा से लेकर वराछा पोद्दार आर्केड तक हर दिन लंबी वाहन कतारें, धीमी रफ्तार और घंटों जाम जैसी स्थिति आम होती जा रही है। अब हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए एक व्यापक और दीर्घकालिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है।

Surat Integrated Transportation Development Corporation Limited यानी SITCO द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना केवल स्टेशन भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एलिवेटेड कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाएं, मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और भविष्य की शहरी जरूरतों को ध्यान में रखकर संपूर्ण क्षेत्र का पुनर्विकास शामिल है। लेकिन इसी निर्माण प्रक्रिया ने शहर के सबसे व्यस्त ट्रांजिट ज़ोन को ट्रैफिक दबाव के बड़े केंद्र में बदल दिया है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सूरत नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर M. Nagarajan और पुलिस कमिश्नर Anupam Singh Gehlot की अध्यक्षता में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology यानी SVNIT के विशेषज्ञों, SITCO अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में प्रस्तुत ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी। SVNIT विशेषज्ञों के अनुसार रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में प्रतिदिन लगभग एक लाख कारों का आवागमन होता है। इसके अलावा हजारों ऑटो रिक्शा, बसें, टैक्सियां और दोपहिया वाहन भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। रेलवे स्टेशन शहर के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन केंद्रों में से एक है, जहां हर दिन भारी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। यही कारण है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में हालात और जटिल हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के सामने बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज के पिलर निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इसके बाद सड़क की उपलब्ध जगह और कम हो जाएगी तथा ट्रैफिक

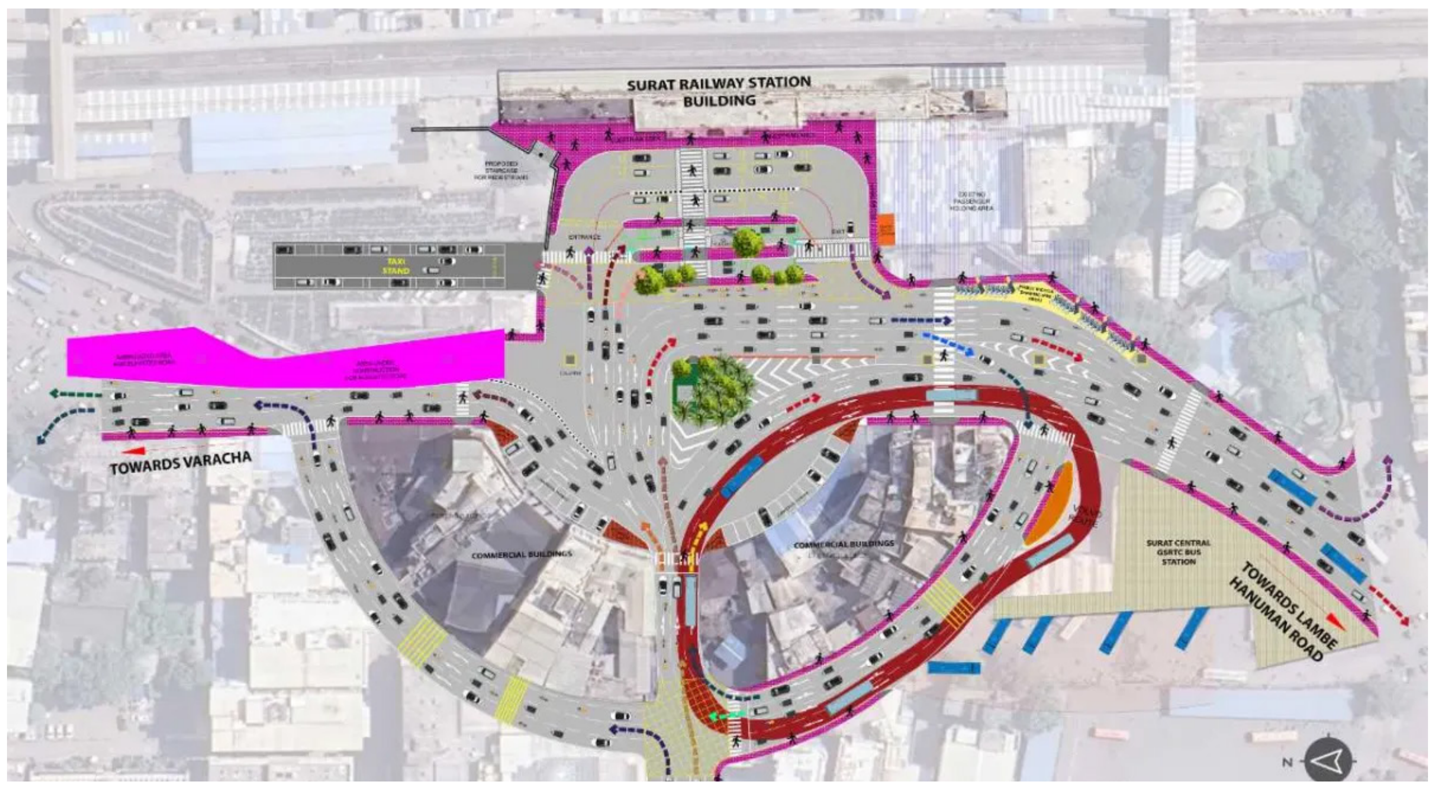

डायवर्जन की आवश्यकता बढ़ेगी। प्रशासन ने इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक नियंत्रण योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

नई योजना के तहत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में वाहनों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग लेन विकसित की जाएंगी। कार, बस और ऑटो रिक्शा के लिए पृथक मार्ग बनाए जाएंगे ताकि मिश्रित ट्रैफिक के कारण बनने वाली अव्यवस्था को रोका जा सके। प्रशासन का मानना है कि अलग लेन सिस्टम लागू होने से वाहन प्रवाह अधिक व्यवस्थित होगा और सड़क पर रुकावटें कम होंगी।

इसके साथ ही पैदल यात्रियों के लिए भी अलग और सुरक्षित मार्ग विकसित किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पैदल आवाजाही करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्हें वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है। इससे दुर्घटना और अव्यवस्था दोनों की आशंका बनी रहती है। नई योजना में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवाजाही को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

प्रशासन ने रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध दबाव और अनियंत्रित पार्किंग को भी ट्रैफिक संकट का बड़ा कारण माना है। अधिकारियों के अनुसार कई निजी वाहन और टैक्सियां लंबे समय तक स्टेशन के सामने खड़ी रहती हैं, जिससे सड़क की क्षमता प्रभावित होती है। अब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध पार्किंग हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

रेलवे स्टेशन परिसर में एयरपोर्ट मॉडल पर "पिक-अप एंड ड्रॉप" सिस्टम लागू करने का निर्णय भी इसी रणनीति का हिस्सा है। नई व्यवस्था के तहत निजी वाहनों को केवल यात्रियों को छोड़ने और लेने के लिए सीमित समय तक प्रवेश मिलेगा। लंबे समय तक वाहन खड़े रखने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि इससे स्टेशन परिसर में भीड़ और पार्किंग दबाव में उल्लेखनीय कमी आएगी।

एक और बड़ा फैसला रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल को लेकर लिया गया है। स्टेशन के सामने प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज के पिलर निर्माण में मौजूदा दीवार बाधा बन रही है। ऐसे में प्रशासन ने बाउंड्री वॉल हटाने का निर्णय लिया है ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ सके। हालांकि इसके साथ सुरक्षा और यात्री प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

रेलवे स्टेशन के बाहर संचालित टैक्सी और ऑटो स्टैंड भी लंबे समय से ट्रैफिक अव्यवस्था की प्रमुख वजह बने हुए हैं। कई बार सड़क पर खड़े वाहन मुख्य मार्ग को संकरा बना देते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। अब प्रशासन ने टैक्सी स्टैंड को जिला पंचायत की जमीन पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इससे मुख्य सड़क पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

साथ ही रिक्शा, बस और कारों के लिए "सिंगल लेन सिस्टम" सख्ती से लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार कई बार वाहन चालक अपनी निर्धारित लेन छोड़कर दूसरी लेन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। अब निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई के जरिए इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।

रेलवे स्टेशन के सामने स्थित ST बस स्टैंड भी ट्रैफिक दबाव का बड़ा कारण माना गया है। लगातार बसों की आवाजाही और सड़क पर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने के कारण पूरे क्षेत्र में जाम की स्थिति बनती है। SVNIT विशेषज्ञों की सलाह पर अब ST बसों के लिए विशेष वन-वे सिस्टम लागू किया जाएगा। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि बसें निर्धारित बस स्टैंड के बाहर सड़क पर न रुकें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना अगले दो से तीन वर्षों तक जारी रहेगी। ऐसे में केवल अस्थायी समाधान पर्याप्त नहीं होंगे। इसी कारण दीर्घकालिक और व्यवस्थित ट्रैफिक प्रबंधन योजना पर काम किया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य और शहर की दैनिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाया जा सके।

सूरत का रेलवे स्टेशन आने वाले वर्षों में शहर की नई पहचान बन सकता है, लेकिन फिलहाल यह परिवर्तन शहर के लिए बड़ी परीक्षा भी बन गया है। प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि विकास कार्य की गति भी बनी रहे और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराने न पाए। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि तैयार किया गया यह मास्टर प्लान तेजी से बढ़ते शहरी दबाव को किस हद तक नियंत्रित कर पाता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा 15/16 मई 2026 की रात्रि में मेजर ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा दादर स्टेशन पर अप एवं डाउन धीमी लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कमीशनिंग कार्य हेतु 15/16 मई, 2026 की मध्यरात्रि को मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक 15/16 मई, 2026 की मध्यरात्रि 00.00 बजे से 05.00 बजे तक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान सभी धीमी लाइन की ट्रेनें मुंबई सेंट्रल एवं माहिम स्टेशनों के बीच फास्ट लाइनों पर चलाई जाएंगी। परिणामस्वरूप, प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता तथा प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण ये ट्रेनें महालक्ष्मी, लोअर परेल, प्रभादेवी, माटुंगा रोड एवं माहिम स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी।

उपरोक्त स्टेशनों तक यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु चर्चगेट से 23.31 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या BA91021 चर्चगेट – बांद्रा, डाउन दिशा की अंतिम ट्रेन होगी, जिसे विरार तक विस्तारित किया जाएगा। इसी प्रकार, बोरीवली से 23.03 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या BO90982 प्रभावित स्टेशनों हेतु अप दिशा की अंतिम ट्रेन होगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। प्रभावित सेवाओं की विस्तृत जानकारी उपनगरीय खंड के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखें।

मदार–पालनपुर रेलखंड पर ब्रिज कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा

उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर रेल मंडल के मदार–पालनपुर रेलखंड पर आउवा एवं भिंवालिया स्टेशनों के मध्य स्थित ब्रिज संख्या 605 पर आरसीसी बॉक्स डालने हेतु आवश्यक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी।

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

- ट्रेन सं. 14822 साबरमती–जोधपुर एक्सप्रेस दिनांक 15.05.2026 और 16.05.2026 को रद्द रहेगी।
- ट्रेन सं. 14821 जोधपुर–साबरमती एक्सप्रेस, दिनांक 14.05.2026 और 15.05.2026 को रद्द रहेगी।

- दिनांक 15.05.2026 की ट्रेन सं. 19223, साबरमती–जम्मू तवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया मेहसाणा–भीलड़ी–लूणी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 15.05.2026 की ट्रेन सं. 12462, साबरमती–जोधपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया मेहसाणा–भीलड़ी–लूणी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 15.05.2026 की ट्रेन सं. 14707, हनुमानगढ़–दादर रणकपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया लूणी–भीलड़ी–मेहसाणा चलेगी।
- दिनांक 14.15.2026 की ट्रेन सं. 20496, हडपसर-जोधपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-भीलड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 14.15.2026 की ट्रेन सं. 20943, बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-भीलड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 14.05.2026 की ट्रेन सं. 14701, श्रीगंगानगर–बान्द्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस, परिवर्तित मार्ग अजमेर–चित्तौड़गढ़–रतलाम–वडोदरा के रास्ते चलेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सूरत से असम तक सेवा का सेतु : 1100 जनजातीय बेटियों के सामूहिक विवाह से जुड़ी संवेदना, संस्कार और सामाजिक एकता की अनोखी मिसाल

Surat की सामाजिक और दानशील परंपरा ने एक बार फिर देश के दूरस्थ हिस्सों तक अपनी मानवीय संवेदनाओं का विस्तार किया है। सेवा, संस्कार और सामाजिक सहयोग की भावना को केंद्र में रखते हुए सूरत की सामाजिक संस्था Purvanchal Samuhik Vivah Anushthan Samiti ने असम के जनजातीय क्षेत्रों में 1100 बेटियों के सामूहिक विवाह का विशाल आयोजन कर एक अनोखी मिसाल पेश की है। यह आयोजन केवल विवाह संस्कार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण और जरूरतमंद परिवारों के सहयोग के बड़े अभियान के रूप में देखा जा रहा है।

संस्था द्वारा वर्षों से पूर्वोत्तर भारत के दूरदराज और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में सेवा कार्य किए जाते रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष असम के चाय बागानों और जनजातीय इलाकों में रहने वाले परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन का उद्देश्य उन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहारा देना था, जिनके लिए पारंपरिक विवाह आयोजन करना कठिन हो जाता है।

कार्यक्रम का संचालन धर्मजागरण समन्वय-सूरत विवाह समिति के प्रमुख Vijay Kumar Chaumal के नेतृत्व में किया गया, जबकि संस्था के संरक्षक Rakesh Kansal का विशेष सहयोग रहा। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार, इस सेवा कार्य का मूल उद्देश्य केवल विवाह संपन्न कराना नहीं, बल्कि जनजातीय समाज में आत्मविश्वास, सम्मान और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना भी है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम असम के कई महत्वपूर्ण जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए। इनमें Tezpur, Tinsukia, Jorhat तथा Karbi Anglong जैसे इलाके प्रमुख रहे। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जो आर्थिक सीमाओं के कारण बेटियों के विवाह को लेकर लंबे समय तक संघर्ष करते हैं। संस्था ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जोड़ा।

आयोजन के दौरान विवाह संस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक विधियों के अनुसार संपन्न कराए गए। स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, ताकि विवाह केवल औपचारिक कार्यक्रम न रहकर सामाजिक उत्सव का रूप ले सके। कई गांवों में इस आयोजन को लेकर उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया और स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक सहयोग की बड़ी पहल बताया।

इस सेवा अभियान में प्रत्यक्ष भागीदारी और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सूरत से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भी असम पहुंचा। चार दिवसीय प्रवास के दौरान राकेश कंसल, उनकी धर्मपत्नी प्रीति बहन, विजय चौमाल तथा Balkishan Agrawal सहित कई पदाधिकारी विभिन्न विवाह स्थलों पर मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय परिवारों से मुलाकात कर उनकी परिस्थितियों को समझा और आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

क्रूड ऑयल वायदा 62 रुपये फिसला: सोना वायदा में 44 रुपये का सुधार: चांदी वायदा में 4357 रुपये की गिरावट

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 498403.99 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 34481.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 463921.72 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 40063 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4222.45 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 23754.47 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 161888 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 163055 रुपये और नीचे में 161027 रुपये पर पहुंचकर, 162186 रुपये के पिछले बंद के सामने 44 रुपये या 0.03 फीसदी की तेजी के संग 162230 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मई वायदा 55 रुपये या 0.04 फीसदी औंधकर 130068 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 8 रुपये या 0.05 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 16294 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 161387 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 162389 रुपये और नीचे में 159526 रुपये पर पहुंचकर, 99 रुपये या 0.06 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 161656 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 161720 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 162551 रुपये और नीचे में 158200 रुपये पर पहुंचकर, 161723 रुपये के पिछले बंद के सामने 197 रुपये या 0.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 161920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 298373 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 299000 रुपये और नीचे में 294450 रुपये पर पहुंचकर, 300238 रुपये के पिछले बंद के सामने 4357 रुपये या 1.45 फीसदी औंधकर 295881 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 3703 रुपये या 1.23 फीसदी की गिरावट के साथ 298431 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 3806 रुपये या

1.26 फीसदी लुढ़ककर 298351 रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 4995.77 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 4.9 रुपये या 0.35 फीसदी घटकर 1394 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 5.1 रुपये या 1.4 फीसदी बढ़कर 369.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 65 पैसे या 0.17 फीसदी की नरमी के साथ 385.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 30 पैसे या 0.15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 204.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 34481.06 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 463921.72 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 23754.47 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40063 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5551.75 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 9706 रुपये के भाव पर खूलकर, 9804 रुपये के दिन के उच्च और 9541 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 62 रुपये या 0.64 फीसदी की गिरावट के साथ 9649 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 65 रुपये या 0.67 फीसदी लुढ़ककर 9646 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 272 रुपये के भाव पर खूलकर, 278.3 रुपये के दिन के उच्च और 271.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 275.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.1 रुपये या 0.76 फीसदी गिरकर 273.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 2.1 रुपये या 0.76 फीसदी औंधकर 273.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 998 रुपये पर खूलकर, 3 रुपये या 0.3 फीसदी घटकर 994 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 12368.03 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11386.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3753.49 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 566.79 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 44.85 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 617.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4118.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1411.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.72 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10974 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62951 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20886 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 269158 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 42491 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8782 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21345 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 68629 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17494 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26519 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा 40038 पॉइंट पर खूलकर, 40063 के उच्च और 40038 के नीचले स्तर को छूकर, 157 पॉइंट घटकर 40063 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 67.5 रुपये की गिरावट के साथ 70.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.1 रुपये की गिरावट के साथ 6.75 रुपये हुआ।

सोना मई 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 53 रुपये की गिरावट के साथ 236 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 318.5 रुपये की गिरावट के साथ 1596 रुपये हुआ। तांबा मई 1450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.53 रुपये की गिरावट के साथ 9.82 रुपये हुआ। जस्ता मई 415 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.99 रुपये की बढ़त के साथ 2 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 30 पैसे के सुधार के साथ 121.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 80 पैसे के सुधार के साथ 8.45 रुपये हुआ।

सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 172.5 रुपये की गिरावट के साथ 581 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 73.5 रुपये की बढ़त के साथ 807.5 रुपये हुआ। तांबा मई 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 29 पैसे की नरमी के साथ 8.23 रुपये हुआ। जस्ता मई 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.4 रुपये की गिरावट के साथ 2.5 रुपये हुआ।

NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक बार फिर सवाल उठे, छात्रों के भविष्य के लिए भ्रष्टाचार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देशभर में लाखों छात्र हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में अथक परिश्रम करते हैं, उज्ज्वल भविष्य के सपने लिए हुए। लेकिन जब इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें सामने आती हैं या पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। इस साल भी, मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर पेपर लीक के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 3 मई को होने वाली परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा, मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

यहां सवाल यह उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में बार-बार अनियमितताएं क्यों होती हैं? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का दावा है कि प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर उन्हें संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने तक पूरी गोपनीयता बरती जाती है। साथ ही, सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है। ऐसे में, परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों के एक विशिष्ट समूह तक कैसे पहुंच जाते हैं? ये बातें क्या संकेत देती हैं? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और जांच एजेंसियां अनियमितताओं के इस बार-बार होने वाले चक्र के मूल कारण या विशिष्ट खामी का पता लगाने में असमर्थ क्यों हैं?

स्पष्टतः, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, उससे जुड़े अन्य संगठनों और "पेपर लीक माफिया" के बीच सांठगांठ के बिना ऐसी घटनाएं संभव नहीं हैं। सरकार को इन परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों द्वारा की गई अथक मेहनत पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वास्तव में, कई परिवार महंगे कोचिंग कार्यक्रमों के लिए अपनी जमीन या गहने तक गिरवी रख देते हैं, जबकि कई छात्र बैंक से ऋण लेते हैं। इसलिए, प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इन छात्रों का भविष्य खतरे में न पड़े।

राजस्थान के दो भाइयों को 30 लाख रुपये में NEET-UG परीक्षा का पेपर खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने बेटे के लिए गुरुग्राम के एक डॉक्टर से यह सौदा किया था। NEET-UG परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान से दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों ने परीक्षा से पहले गुरुग्राम के एक डॉक्टर से यह पेपर प्राप्त किया था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान के जामवा रामगढ़ निवासी मंगिलाल और दिनेश बिवाल ने परीक्षा से पहले 26 अप्रैल को 30 लाख रुपये में यह पेपर खरीदा था। इनमें से एक भाई ने यह पेपर अपने बेटे को दिया, जो राजस्थान के सीकर में मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

29 तारीख को यह पेपर एक और छात्र को बेचा गया और उसके बाद यह पेपर हर जगह फैल गया। यह भी सामने आया है कि इन भाइयों में से एक के राजनीतिक संबंध हैं। वह डॉक्टर कौन है? रहस्य अभी भी बना हुआ है। एमबीबीएस मेडिकल में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलता है जो विज्ञान विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और अच्छे अंकों से NEET परीक्षा पास करते हैं। और इस मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए NEET में भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। और मेडिकल में शॉर्टकट के तौर पर प्रवेश पाने के लिए, कुछ माता-पिता लाखों रुपये खर्च करके NEET के पेपर खरीदते हैं ताकि उनके बच्चे डॉक्टर बन सकें। छात्र पूरी तरह निर्दोष हैं लेकिन उनके माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए ऐसे अवैध कृत्यों का सहारा लेते हैं। यह भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है?

बारहवीं की परीक्षा में वही विषय होते हैं जो NEET परीक्षा में होते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर NEET के बिना बारहवीं की परीक्षा के नतीजों के आधार पर MBBS और मेडिकल में दाखिला दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर बारहवीं में अच्छे नंबर आए हैं तो NEET में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर बारहवीं में साइंस में कम नंबर आए हों और मेडिकल में जाना चाहते हों तो NEET जैसी भ्रष्ट परीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। क्या NEET परीक्षा से पहले दाखिला लेकर डॉक्टर बने लोग होशियार नहीं थे?

सूरत में पेट्रोल–डीजल की कमी के कारण आधे से अधिक पेट्रोल पंप बंद हो गए, सरकारी पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर और जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण सरकारी तेल कंपनियों के आधे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं और पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें फिर से देखी जा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए दक्षिण गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सूरत जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सूरत कलेक्टर ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों को बुलाकर मामले का संज्ञान लिया और आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि, निजी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के कारण, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सरकारी पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ गई।

इसी वजह से पिछले तीन दिनों से सरकारी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। सूरत शहर और जिले के आधे से अधिक पेट्रोल पंप बंद हैं और बाकी बचे पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है।

यह जानकारी मिली है कि इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए, आपूर्ति अधिकारी ने प्रत्येक अधिकारी से उस क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर मौजूद वस्तुओं की स्टॉक सूची का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट भी मांगी है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य के वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया, राज्य मंत्री श्री प्रवीणकुमार माळी ने सासन गिर में आयोजित समिट में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होगी पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट

▶▶ भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समिट के पूर्वार्ध के रूप में भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक और चंद्रपुर में प्री-इवेंट आयोजित किए जाएंगे

▶▶ सासन गिर में लायन कंजर्वेशन पर प्री-इवेंट आयोजित हुई

▶▶ एशियाटिक लायन-गिर के शावक के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के सफल प्रयासों से प्रधानमंत्री ने 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र को साकार किया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ वनराज की गौरवशाली विरासत को बनाए रखते हुए वन्यजीवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया 'प्रोजेक्ट लायन' सफल रहा है

▶▶ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए 'जीव में शिव' और 'पौधों में परमात्मा' की संस्कृति का विश्व को दर्शन कराएगी

▶▶ सिंह संरक्षण को प्राथमिकता और वन विभाग की बेहतरीन कार्यप्रणालियों के परिणामस्वरूप सिंहों की संख्या और उनके विचरण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है

▶▶ इकोलॉजी के साथ इमोशन जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण गुजरात में चरितार्थ हो रहा है

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 1 जून 2026 को नई दिल्ली में आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा : केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव

▶▶ गुजरात का सिंह संरक्षण का उत्कृष्ट रोल मॉडल विश्व के सामने वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, बिग कैट वर्ग की 7 प्रजातियों में से 5 भारत में पाई जाती हैं; यह देश का गौरव है : केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव

▶▶ गुजरात की भूमि पर बाघ का स्थायी निवास सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग तैयार है, बरडा सिंहों का दूसरा आवास बन चुका है : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

गांधीनगर, 14 मई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आईबीसीए समिट भारत-2026 के पूर्वार्ध के रूप में सासन गिर में आयोजित पहली 'प्री-इवेंट लायन कंजर्वेशन' का गुरुवार को गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि एशियाटिक लायन यानी गिर के शावकों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के सफल प्रयासों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार किया है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य के वन मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया और राज्य मंत्री श्री प्रवीणकुमार माळी इस प्री-इवेंट में सासन गिर में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से आगामी 1 और 2 जून को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली समिट आयोजित होगी। इस समिट की प्री-इवेंट्स देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग थीम पर आयोजित की जाएंगी। इसके अंतर्गत सासन गिर में सिंह, भोपाल में चीता, भुवनेश्वर में तेंदुआ, गंगटोक में स्नो लेपर्ड तथा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने सासन गिर की इस प्री-इवेंट को बिग कैट संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री के विजन को समझने का उत्कृष्ट स्थल बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने गिर अभयारण्य और सिंहों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाए, उनके अनुभव से देश में बिग कैट संरक्षण को नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी के साथ इमोशन जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण गुजरात में चरितार्थ हुआ है।

सिंह संरक्षण को प्राथमिकता और वन विभाग की बेस्ट प्रो एक्टिव प्रेक्टिसिस के परिणामस्वरूप सिंहों की संख्या 1991 में 284 से बढ़कर आज लगभग 891 हो गई है।

इतना ही नहीं; सिंहों के विचरण क्षेत्र का विस्तार भी पिछले ढाई दशकों में तीन जिलों से बढ़कर 11 जिलों तक पहुंच गया है। पोरबंदर के बरडा क्षेत्र में सिंहों का प्राकृतिक आगमन हुआ है और सरकारी प्रयासों से बरडा अभयारण्य एशियाटिक लायन का नया आवास बन चुका है। वर्तमान में लगभग 24 सिंह बरडा में निवास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विस्तृत भूमिका दी कि वनराज की गौरवशाली विरासत को बनाए रखने और वन्यजीवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2000 करोड़ रुपए की 'प्रोजेक्ट लायन' योजना शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि सिंहों के लिए ब्रीडिंग सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, उपचार केंद्रों का आधुनिकीकरण, रेडियो कॉलर और ड्रोन सर्विलांस जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रोजेक्ट लायन' केवल सिंह संरक्षण ही नहीं बल्कि 'बृहद गिर' क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा स्थानीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आयोजित यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए 'जीव में शिव' तथा 'पौधों में परमात्मा' की भारतीय संस्कृति का विश्व को परिचय कराएगी।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव

केंद्रीय वन और पर्यावरण तथा जलवायु मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट के संदर्भ में कहा कि, भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में प्रकृति, पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नया विजन प्रस्तुत किया है।

बिग कैट अर्थात बिल्ली कुल के प्रमुख वन्य प्राणियों सहित अन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट के माध्यम से मंथन किया जाएगा और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आधार स्तंभ के रूप में 'दिल्ली डिक्लेरेशन' भी जारी किया जाएगा।

इस समिट में विश्व के नीति-निर्माता, वन्यजीव क्षेत्र के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, कॉर्पोरेट जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग भाग लेंगे। इससे वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सहयोग और अधिक सुदृढ़ बनेगा।

इस समिट की थीम भी बिल्ली कुल के वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा मानवता और पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण पर आधारित रहेगी।

उन्होंने उद्घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) की परिकल्पना और पहल वर्ष 2023 में की गई थी। अब 1 जून 2026 को उनके मार्गदर्शन में आईबीसीए शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। बिल्ली कुल की ये सात प्रजातियां विश्व के 55 देशों में पाई जाती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात ने पूरे विश्व के सामने सिंह संरक्षण का उत्कृष्ट रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। जबकि पूरे विश्व में अफ्रीकी लायन सहित अन्य सिंहों की संख्या घट रही है, वहीं एशियाई शेरों की आबादी में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 891 हो गई है। सिंहों के संरक्षण के लिए नए आवास क्षेत्र भी विकसित किए गए हैं, जिनमें बरडा अभयारण्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया है। सौराष्ट्र और गुजरात की जनता के सम्मान के प्रतीक बने सिंह तथा उनके संरक्षण के इस मॉडल को हम पूरे विश्व के सामने आगे बढ़ाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि मनुष्य हर वस्तु का निर्माण कर सकता है, लेकिन जीव का निर्माण नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति भी करुणा के गुण पर विशेष बल देती है, अर्थात पूरी पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त जीव-जगत के लिए भी है, इसलिए उसका संरक्षण करना उतना ही आवश्यक है।

उन्होंने प्रगति के लिए आर्थिक विकास के साथ-साथ इकोसिस्टम के संरक्षण पर भी बल देते हुए कहा कि जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है।

इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने सासन की भूमि पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्री-इवेंट आयोजित किए जाने का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात की धरती पर बिल्ली कुल के प्रमुख वन्य प्राणी जैसे सिंह और तेंदुआ पहले से ही पाए जाते हैं, और अब इसमें वृद्धि करते हुए रतन महाल अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति भी देखी गई है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बाघ का गुजरात की धरती पर स्थायी निवास सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि चीते को भी गुजरात में लाने की तैयारी वन विभाग द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में पर्यावरण संरक्षण के साथ इकोसिस्टम भी मजबूत हुआ है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के निदेशक एस.पी. यादव ने वीडियो फिल्म प्रस्तुति के माध्यम से आईबीसीए की पृष्ठभूमि तथा बिल्ली कुल के सात प्रमुख वन्य प्राणियों की वैश्विक उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व के सात बिग कैट में बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा शामिल हैं। इनमें से पांच — बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं।

सासन गिर में आयोजित इस प्री-इवेंट में सासन की वन्य जीव-सृष्टि और संरक्षण से संबंधित ब्रोशर का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर वन राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर सचिव श्री आर.सी. मीणा, डॉ. ए.पी. सिंह, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉ. जयपाल सिंह, बी.पी. पाटी, श्री रमेश कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सीसीएफ डॉ. राम रतन नाला के मार्गदर्शन में सासन वन विभाग की टीम ने पूरे कार्यक्रम का समन्वय किया।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास रहने वाले 1000 आदिवासी परिवार रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास रहने वाले 1000 आदिवासी परिवारों के घरों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी

▶▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं योजनाएं

गांधीनगर : दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) के आसपास रहने वाले लगभग 1000 आदिवासी परिवार रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर हैं। राज्य सरकार द्वारा 1000 आदिवासी परिवारों को बायोगैस प्लांट प्रदान करने के लिए की गई मेहनत अब रंग ला रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2025 में एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास रहने वाले 1000 आदिवासी घरों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी।

यह योजना नर्मदा जिले की गरुड़ेश्वर तहसील की 38 ग्राम पंचायतों के 89 गांवों में लागू की जा रही है। गरुड़ेश्वर तहसील पंचायत द्वारा क्रियान्वित इस योजना की निगरानी जिला ग्राम विकास एजेंसी (डीआरडीए) द्वारा की जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य एलपीजी और परंपरागत लकड़ी के ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 7 किमी दूर स्थित वाघपुरा गांव निवासी रवि तड़वी ने कहा कि सरकार द्वारा स्थापित किए गए बायोगैस प्लांट के कारण उनके दैनिक जीवन में बड़ा बदलाव आया है। रवि तड़वी ने आगे कहा, "अब हमें एलपीजी सिलेंडर की चिंता नहीं रहती। बायोगैस प्लांट के जरिए रोजाना स्वच्छ ईंधन मिलता है और बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी खेती में रासायनिक खाद का उत्तम विकल्प बन गई है। जैविक खाद के उपयोग के कारण फसल का उत्पादन भी अधिक होता है।"

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए स्थानीय निवासी चंदू तड़वी ने योजना से महिलाओं के जीवन पर पड़े सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया, "बायोगैस प्लांट के कारण महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हुआ है। पहले वे खेत में काम करने के बाद लकड़ी इकट्ठा करने के लिए दूरदराज के स्थानों तक जाती थीं। चूल्हे पर रसोई पकाने के कारण धुआं निकलता था और आंखों को नुकसान होता था। लेकिन, अब बायोगैस के उपयोग के कारण उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है और वे रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन गई हैं।"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। गुजरात में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। अब तक 665 से अधिक बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और बाकी प्लांट लगाने का काम प्रगति पर है। प्लांट को स्थापित करने का पूरा खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है। लाभार्थी को प्लांट स्थापित करने के लिए जरूरी गड्ढा खोदने के लिए श्रमदान करना होता है।

बायोगैस प्लांट से महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस मिलती है, साथ ही प्लांट से निकलने वाली स्लरी का उपयोग खेती में खाद के रूप में होने से विदेश से आयात होने वाले रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होती है।

हजीरा से वैश्विक स्टील मानचित्र तक : AM/NS India ने EQ70 वेल्डेड पाइप्स बनाकर रचा नया औद्योगिक इतिहास

Surat के औद्योगिक परिदृश्य में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। हजीरा स्थित संयंत्र में AM/NS India ने अत्याधुनिक EQ70 अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ वेल्डेड पाइप्स का सफल उत्पादन कर भारतीय स्टील और पाइप निर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। कंपनी की यह उपलब्धि केवल तकनीकी सफलता नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील के संयुक्त उद्यम AM/NS India ने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यानी SAW तकनीक के माध्यम से इन अत्याधुनिक पाइप्स का निर्माण किया है। कंपनी के अनुसार यह विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली उपलब्धि है, जिसमें EQ70 ग्रेड के अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ वेल्डेड पाइप्स को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया गया है।

इस उपलब्धि को और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन पाइप्स को American Bureau of Shipping यानी ABS से आधिकारिक प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ABS को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित समुद्री और ऑफशोर सुरक्षा प्रमाणन संस्थाओं में गिना जाता है। इसका प्रमाणन इस बात का संकेत है कि ये पाइप्स अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और इंजीनियरिंग मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं और इन्हें समुद्री तथा ऑफशोर परियोजनाओं में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में भारत में केवल वही ऐसी कंपनी है, जो EQ70 ग्रेड के इस स्तर के वेल्डेड पाइप्स का निर्माण कर रही है। इससे पहले इस श्रेणी के हाई-स्ट्रेंथ

पाइप्स के लिए भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों और आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। अब यह तकनीक देश में विकसित होने से भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इन पाइप्स का उपयोग मुख्य रूप से तेल और गैस उद्योग में लंबी दूरी की पाइपलाइन परियोजनाओं में किया जाता है। इसके अलावा ऑनशोर और ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपवॉटर पाइपलाइन, जैक-अप रिग्स और कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी इनका उपयोग बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ऊर्जा और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में ऐसे हाई-स्ट्रेंथ पाइप्स की मांग तेजी से बढ़ेगी।

कंपनी के अनुसार EQ70 दरअसल API 5L X100Q के समकक्ष हाई-स्ट्रेंथ लो-अलॉय स्टील ग्रेड है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्यधिक मजबूती और टिकाऊ क्षमता है। इसमें न्यूनतम 690 MPa यील्ड स्ट्रेंथ के साथ बेहतरीन टफनेस मौजूद होती है, जिससे यह अत्यधिक दबाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के पाइप्स का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें अपेक्षाकृत पतला और हल्का बनाया जा सकता है, जबकि उनकी मजबूती बनी रहती है। इससे परियोजनाओं की लागत कम होती है और पाइपलाइन सिस्टम अधिक कुशल बनता है। इसके अलावा इन पाइप्स की उन्नत वेल्डेबिलिटी और जंग-प्रतिरोध क्षमता इन्हें समुद्री क्षेत्रों और खारे वातावरण में लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखती है। यह उपलब्धि भारत सरकार की Make in India पहल के लिए भी बड़ी सफलता मानी जा रही है। लंबे समय से भारत हाई-स्ट्रेंथ पाइप्स के लिए यूरोपीय और अन्य विदेशी बाजारों पर निर्भर रहा है। अब देश में ही इस स्तर की तकनीक और उत्पादन क्षमता विकसित होने से न केवल आयात में कमी आएगी, बल्कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इस परियोजना को कॉन्सेप्ट से लेकर ABS प्रमाणन तक पहुंचाने में लगभग 12 महीनों का समय लगा। इस दौरान लगातार तकनीकी परीक्षण, प्रक्रिया सुधार और कठोर गुणवत्ता जांच की गईं। इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि पाइप्स अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों और हर स्तर पर सुरक्षा तथा प्रदर्शन की कसौटी पर खरे उतरें।

AM/NS India के अनुसार अब कंपनी वैश्विक ऑफशोर और मरीन बाजारों में EQ70 वेल्डेड पाइप्स की आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को विश्वसनीय सप्लाई चेन उपलब्ध होगी और कई देशों के लिए लागत में कमी का विकल्प भी खुलेगा।

इस उपलब्धि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस खोज परियोजनाएं बढ़ रही हैं, वहीं टिकाऊ और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत में विकसित यह तकनीक देश को वैश्विक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में नई स्थिति प्रदान कर सकती है।

कंपनी ने भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। AM/NS India ने बताया कि उसकी पाइप मिल अब SAW तकनीक के माध्यम से हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशेष पाइप ग्रेड विकसित करने पर काम कर रही है। इसे स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दुनिया भर में हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है और उसके सुरक्षित परिवहन के लिए विशेष पाइपलाइन तकनीक की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इस क्षेत्र में भी तकनीकी बढ़त हासिल कर लेता है, तो वह वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की दौड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। AM/NS India की वर्तमान उपलब्धि को इसी भविष्य की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है।

कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य केवल स्टील उत्पाद बनाना नहीं, बल्कि ऊर्जा, समुद्री और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए स्मार्ट और टिकाऊ समाधान विकसित करना है। "स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स" के विजन के साथ कंपनी लगातार नई तकनीकों और उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों पर कार्य कर रही है।

फियो ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की यूएई और यूरोप की बहु-राष्ट्रीय यात्रा का स्वागत किया, भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई

नई दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने 15-20 मई, 2026 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आगामी आधिकारिक यात्रा का स्वागत किया है। फियो ने कहा कि यह यात्रा प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी को काफी मजबूत करेगी और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।

इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस.सी. रल्हन ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है, जब भारत बेहतर व्यापारिक साझेदारियों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश-आधारित विकास के माध्यम से यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक एकीकरण को गहरा कर रहा है।

श्री रल्हन ने कहा, " यूएई और प्रमुख यूरोपीय देशों के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की उच्च-स्तरीय वार्ताएं एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार और वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करती हैं। इस यात्रा से

इंजीनियरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा होने की उम्मीद है।"

यूएई की प्रधानमंत्री की यात्रा का स्वागत करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध तेजी से बढ़ते व्यापार और निवेश संपर्कों के साथ एक मजबूत 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूएई भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश साझेदारों में से एक बना हुआ है और मध्य पूर्व तथा अफ्रीका में भारतीय निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार का काम करता है।

उन्होंने आगे कहा, "यह यात्रा भारत-यूएई के आर्थिक संबंधों को विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, बुनियादी ढांचे, निवेश और सेवाओं के व्यापार के क्षेत्रों में और मजबूत करेगी। यूएई में रहने वाला विशाल भारतीय समुदाय भी व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है।"

नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में प्रधानमंत्री की वार्ताओं पर टिप्पणी करते हुए, फियो अध्यक्ष ने कहा कि यूरोप भारत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात स्थलों और निवेश के स्रोतों में से एक बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हाल ही में संपन्न हुए भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते और भारत-इएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीइपीए) की पृष्ठभूमि में इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

श्री रल्हन ने कहा, "यूरोपीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की चर्चाओं से ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, एआई, इनोवेशन, स्वच्छ तकनीकें, रक्षा निर्माण, ब्लू इकॉनमी, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं और सस्टेनेबिलिटी जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों और उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं।"

ओस्लो में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि नॉर्डिक क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तकनीकों, समुद्री क्षेत्रों, डिजिटल इनोवेशन और उन्नत निर्माण में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, "भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ता रणनीतिक तालमेल भारतीय व्यवसायों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी साझेदारियों के लिए नए रास्ते खोल सकता है, साथ ही भारत के सतत और हरित विकास की ओर परिवर्तन में भी सहायता कर सकता है।"

फियो ने उद्योग के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन और भारत-नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन सहित प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री की भागीदारी का स्वागत किया और कहा कि इस तरह की बातचीत से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और मजबूत औद्योगिक साझेदारियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

श्री रल्हन ने आगे कहा, "इस यात्रा के दौरान शामिल देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार सामूहिक रूप से 70 बिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि इन क्षेत्रों से भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। यह यात्रा द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।"

फियो अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को और बढ़ाएगी, भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करेगी और देश के दीर्घकालिक निर्यात विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देगी।

पश्चिम रेलवे मुंबई और गोरखपुर के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन,दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई एवं गोरखपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी तथा दो मौजूदा स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09157/09158 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर–बोरीवली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से रविवार, 17 मई, 2026 को 00.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 17.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर–बोरीवली स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से सोमवार, 18 मई, 2026 को 20.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा बुधवार को 11.30 बजे बोरीवली पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन मार्ग में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बरेली सिटी, इज्जतनगर, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती तथा खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर–बोरीवली स्पेशल ट्रेन गोरखपुर और बोरीवली के बीच समान मार्ग के स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में स्लीपर तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेनों के फेरे विस्तारित

1. ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 20 मई, 2026 को चलाया जाएगा। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम–मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 21 मई, 2026 को चलाया जाएगा।

2. ट्रेन संख्या 09447/09448 अहमदाबाद–पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद–पटना स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 20 मई, 2026 को चलाया जाएगा। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09448 पटना–अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 22 मई, 2026 को चलाया जाएगा।

ट्रेन संख्या 09157 तथा ट्रेन संख्या 09075 एवं 09447 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 15.05.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।